

जिला सैक्टर योजना/आयोजनागत/एस०सी०एस०पी०

संख्या- ४५० /XV-2/01(05)/2006

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,(नैनीताल एवं बागेश्वर को छोड़कर)
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग- 02

देहरादून, दिनांक 21 जून, 2011:

विषय :- वित्तीय वर्ष 2011-12 में डेरी विकास विभाग को जिला योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण (एस०सी०एस०पी०) हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-755/XV-2/01(05)/2006, दिनांक 10 जून, 2011 द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 में डेरी विकास विभाग को जिला योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण (एस०सी०एस०पी०) हेतु जनपदवार ₹ 56.62 लाख (₹ ५६.६२ लाख बासठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 10 जून, 2011 में अंकित प्रस्तर-02 के स्थान पर निम्नानुसार प्रस्तर-02 पढ़ा जाय:-

2-उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में अनुदान संख्या-30 के अंतर्गत लेखाशीषक-2404-डेरी विकास-00-आयोजनागत-102-डेरी विकास परियोजनाये-02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-0291-ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण (जिला योजना)-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नाम डाला जायेगा।

उक्त शासनादेश दिनांक 10-06-2011 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शार्ट पूर्ववत् रहेंगी।

भवदीय,

/

(विनोद फोनिया)

सचिव।

संख्या : ४५० /XV-2/01(05)2006 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, ओबराय मोर्टस बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड। (नैनीताल एवं बागेश्वर को छोड़कर)
4. स्टाफ ऑफिसर-प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास विभाग को अवगत कराने हेतु।
5. निजी सचिव-मंत्री, डेरी विभाग को माठ मंत्री जी को अवगत कराने हेतु।
6. निदेशक, डेरी विकास विभाग, मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)।
7. समस्त सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग-4/नियोजन विभाग/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एनोआईसी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(जी०बी० ओली)
संयुक्त सचिव।